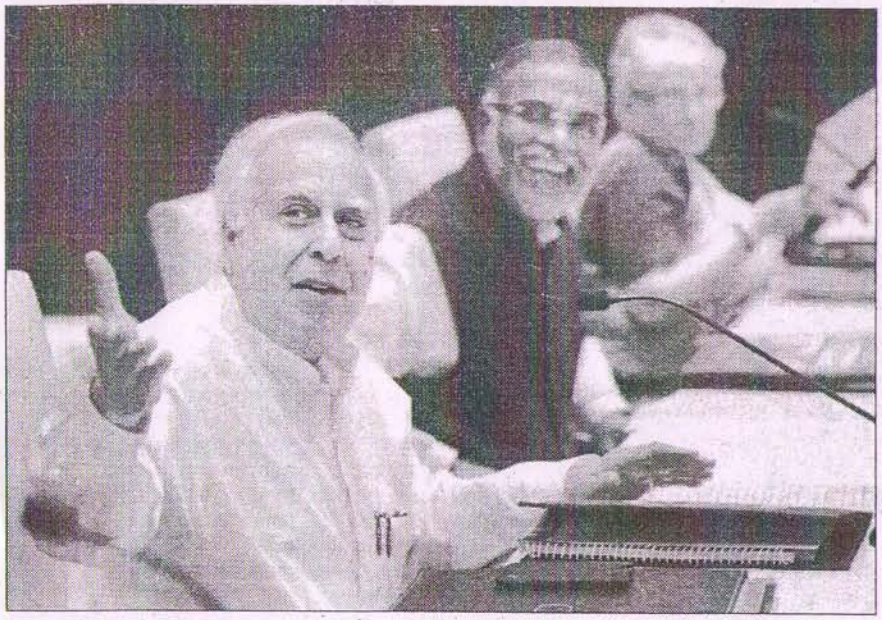

नई दिल्ली में केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की बैठक में शिरकत करते मानव संसाधन विकास मंत्री कपिल सिब्बल और योजना आयोग के सदस्य नरेंद्र जाधव (दाएं)।

राष्ट्रीय शिक्षक मिशन की स्थापना होगी

केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड में कपिल सिब्बल की घोषणा

नई दिल्ली (एसएनबी)। शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के लिए 6 हजार करोड़ रुपए से राष्ट्रीय शिक्षक मिशन की स्थापना होगी ताकि पढ़ाई के लिए सर्वश्रेष्ठ एवं प्रतिभाशाली शिक्षकों को तैयार किया जा सके। यह जानकारी केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड (केब) की बैठक में मानव संसाधन विकास मंत्री कपिल सिब्बल ने दी।

शिक्षकों की कमी और शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए सिब्बल ने कहा कि 12वीं पंचवर्षीय योजना में 6 हजार करोड़ रुपए से एक ऐसे शिक्षक मिशन की स्थापना होने जा रही है जिसमें राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षकों की कमी और उनके प्रशिक्षण आदि पर काम होगा। उन्होंने बताया कि 12 मार्च को संसद के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति प्रतिभा देवी पाटिल ने इस तरह के शिक्षक मिशन की आवश्यकता का जिक्र किया था। उसके बाद ही 17 अप्रैल को राज्यों के शिक्षा सचिवों के साथ दिल्ली में हुई बैठक में राष्ट्रीय शिक्षक मिशन की स्थापना पर चर्चा की गई थी। इस मिशन की स्थापना के बाद शिक्षकों को बदली हुई परिस्थितियों के हिसाब से प्रशिक्षण दिए जाएंगे और शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारा जाएगा।

शिक्षकों की कमी का जिक्र करते हुए सिब्बल ने कहा कि शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार न हो पाने का एक कारण यह भी है। इस समय 12 लाख 60 हजार शिक्षकों की कमी केवल प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर है और शिक्षा का अधिकार कानून आने के बाद 5 लाख 10 हजार शिक्षकों की अतिरिक्त आवश्यकता

▶ छात्रों को फेल न करने के फैसले की समीक्षा होगी

होगी। इसी तरह उच्च शिक्षा में भी 40 फीसद तक शिक्षकों के पद खाली है। शिक्षकों का राष्ट्रीय मिशन इस दिशा में भी राज्यों को समय समय पर दिशा निर्देश देता रहेगा।

अनिवार्य शिक्षा कानून के तहत छात्रों को फेल न करने वाले मामले पर सिब्बल ने कहा कि इस तरह के छात्रों की समीक्षा करने के लिए स्कूलों में शिक्षकों की एक समिति बनेगी और कमजोर छात्रों को अतिरिक्त कोर्स कराया जाएगा ताकि उनमें पढ़ाई के प्रति दबाव बनाया जा सके। कुछ मामलों में देखा गया है कि फेल न होने के भय से छात्रों में पढ़ाई की आदत समाप्त हो रही है और मेधावी छात्रों में इसका गलत असर पड़ रहा है। इसलिए अब ऐसे कमजोर छात्रों की समीक्षा होगी और उनके अभिभावकों को इसकी जानकारी दी जाएगी ताकि शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हो सके।

छात्रों द्वारा बीच में पढ़ाई छोड़ने की समस्या को भी एक चुनौती बताते हुए सिब्बल ने कहा कि निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा कानून को लागू करने में कुछ दिक्कतें आ रही हैं, इनके दूर होने के बाद छात्रों द्वारा बीच में पढ़ाई छोड़ने की समस्या में कमी आएगी। इस काम में समाज को भी अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी क्योंकि यह चुनौती देश के भविष्य के साथ ताल्लुक रखती है।

बैठक में शिक्षा का अधिकार, सर्व शिक्षा अभियान, मेरा विश्वविद्यालय, सूचना प्रौद्योगिकी, क्रेडिट गारंटी फंड पर भी चर्चा हुई। केब की बैठक में राज्यों के शिक्षा मंत्रियों व शिक्षा सचिवों के अलावा योजना आयोग के सदस्य ने भी विचार व्यक्त किए। बैठक में अधिकांश राज्यों ने शिक्षा के बजट में केंद्र के हिस्से की समय पर अदायगी करने की मांग की।